भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2117

उत्तर देने की तारीख- 12/02/2026

वन अधिकार अधिनियम डिजिटल प्लेटफॉर्म

†2117. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री लुम्बाराम चौधरी:
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री गोडम नागेश:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) प्रस्तावित राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार दावों को दर्ज करने, पता लगाने और सत्यापित करने के लिए मॉड्यूल सहित प्रमुख घटक और प्रक्रियात्मकताओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) आगामी दो महीनों में एकीकृत मंच को शुरू करने के लिए कार्यान्वयन की रूपरेखा और उक्त मंच के सह-विकास और परीक्षण के लिए सभी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन-2025 फाइनलिस्टों को शामिल करने के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अग्रणी दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है;
(ग) वन अधिकार समितियों (एफआरसी) और सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समितियों (सीएफआरएमसी) के साथ जमीनी स्तर पर सत्यापन के लिए नासिक जिले के सुरगाणा और इगतपुरी ब्लॉकों में 2-3 जनवरी 2026 को आयोजित क्षेत्र दौरों और प्रमुख परिणाम का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या तेलंगाना के अनुसूचित क्षेत्रों, विशेषकर आईटीडीए क्षेत्रों में उक्त प्रकार के प्रायोगिक परीक्षण, क्षेत्र सत्यापन या क्षमता निर्माण अभ्यास प्रस्तावित हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी समय सीमा और कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), "अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए नवाचार-संचालित पहलों में सक्रिय रूप से संलग्न रहा है। इस संदर्भ में, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (एसआईएच) 2025 के सॉफ्टवेयर श्रेणी के तहत, एमओटीए ने व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर),

सामुदायिक अधिकार (सीआर) और सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) अधिकारों की एकीकृत निगरानी की सहायता करने के लिए एक एआई-संचालित एफआरए एटलस और एक वेबजीआईएस-आधारित निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) के विकास के लिए एक समस्या विवरण प्रस्तुत किया। कुल 390 टीमों ने भाग लिया और शीर्ष पांच टीमों का चयन किया गया। इसके अलावा, एमओटीए ने 2 से 6 जनवरी 2026 तक एक पोस्ट-हैकाथॉन कार्यान्वयन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शीर्ष पांच टीमों के छात्रों और मार्गदर्शकों (मेंटर्स) ने राष्ट्रीय स्तर के एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए मिलकर काम किया।

हैकथॉन के बाद के कार्यान्वयन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, प्रस्तावित राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म के साक्ष्य-आधारित डिजाइन को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक जिले में 2 और 3 जनवरी 2026 के दौरान दो दिवसीय क्षेत्र दौरा आयोजित किया गया था। शीर्ष पांच टीमों के छात्रों और सलाहकारों के समूह ने एमओटीए अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर नासिक जिला कलेक्टर कार्यालय में नासिक जिला स्तरीय समिति के साथ पहली बार बातचीत की, जहां राज्य सरकार ने महाराष्ट्र एफआरए पोर्टल का प्रदर्शन किया, जिसमें इसकी कार्यात्मक संरचना, एफआरए कार्यान्वयन और निगरानी में इसकी व्यावहारिक उपयोगिता और राज्य से उभरने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं (पद्धतियों) पर प्रकाश डाला गया, जिसमें मान्यता प्राप्त पट्टा धारकों की सफलता की कहानियां और पूरे महाराष्ट्र में एफआरए कार्यान्वयन की समग्र स्थिति शामिल है। इसके बाद, समूह ने जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सुरगाणा ब्लॉक के जामुनपाड़ा और सुलपाड़ा गांव तथा नासिक के इगतपुरी ब्लॉक के वाडीवरहे गांव का दौरा किया, जहां छात्रों ने व्यक्तिगत वन अधिकार धारकों, वन अधिकार समितियों (एफआरसी), सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन समितियों (सीएफआरएमसी), वन विभाग के अधिकारियों, ग्राम सभा सदस्यों, आईटीडीपी कलवान और आईटीडीपी नासिक के अधिकारियों के साथ बातचीत की, जमीनी स्तर की चुनौतियों पर चर्चा की, क्षेत्र स्तर के आंकड़ों का सत्यापन किया, प्लेटफॉर्म अंशांकन के लिए क्षेत्र कार्यप्रवाह और भू-स्थानिक आंकड़े एकत्र किये और यह सुनिश्चित किया कि डिजिटल समाधान दावेदारों की वास्तविकताओं में मजबूती से निहित हों।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) में 5 और 6 जनवरी 2026 को दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान, सभी टीमों ने प्रस्तावित राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म के कार्यात्मक डिजाइन और सिस्टम आर्किटेक्चर को परिष्कृत, एकीकृत और अंतिम रूप देने के लिए काम किया, जिसका केंद्र बिंदु कई नवीन समाधानों को एक एकल, स्केलेबल और दावेदार-केंद्रित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य स्थापित करना था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के बाद एमओटीए छात्रों की टीमों को शामिल करने वाला पहला मंत्रालय बन गया। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर के एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास प्रारंभिक चरण में है।

(घ): यह मामला जनजातीय कार्य मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

*****